भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *357
(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत सभी के लिए आवास

***357. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:**
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 'सभी के लिए आवास' पहल के उद्देश्य की स्थिति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार खंडवा , संघ राज्यक्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा छत्रपति संभाजी नगर सहित महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने आवासों/आवासीय इकाइयों को पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया था और कितने पूर्ण किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन में कोई कमियां पाई गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत ''सभी के लिए आवास" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 357 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है , जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है। पीएमएवाई-जी के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित 3.79 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में 20.03.2025 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 3.57 करोड़ लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए है, 3.24 करोड़ लाभार्थियों को सहायता की पहली किस्त जारी की गई है, 2.87 करोड़ लाभार्थियों को सहायता की दूसरी किस्त जारी की गई है और 2.72 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

(ख): पीएमएवाई-जी के तहत, मंत्रालय राज्य को एक इकाई मानकर लक्ष्य आवंटित करता है और राज्य सरकार द्वारा जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत-वार लक्ष्य तय किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों 2021-22 से 2023-24 के दौरान 20.03.2025 की स्थिति के अनुसार खंडवा, संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और छत्रपति संभाजी नगर सहित महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण करने के लिए लक्षित और साथ ही पूर्ण किए गए आवासों/आवास इकाइयों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ): पीएमएवाई-जी को जिन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ा है उनमें कोविड-19 की वजह से लागू प्रतिबंधों के कारण आवासों के निर्माण में देरी, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से राज्य के कोष से पीएमएवाई-जी के राज्य नोडल खाते में केंद्रीय और राज्य अंश जारी करने में देरी, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन में देरी, लाभार्थियों की अनिच्छा के मामले, स्थायी पलायन, विवादित उत्तराधिकार, निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता और कभी-कभी आम/विधानसभा/पंचायत चुनाव शामिल हैं।

मंत्रालय पीएमएवाई-जी के तहत आवासों का समय पर निर्माण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रहा है:

i. मंत्रालय के स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा।
ii. योजना की निगरानी और देखरेख के लिए विशिष्ट पीएमएवाई-जी विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड की शुरूआत।

iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन और पर्याप्त निधियां जारी करना।

iv. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि का प्रावधान और केन्द्रीय एवं राज्य अंश जारी करना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करना।

v. निष्पादन सूचकांक डैशबोर्ड के आधार पर सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों को पुरस्कार प्रदान करना, जिससे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा उत्पन्न हो सके।

अनुबंध

"प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत "सभी के लिए आवास" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 357 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों 2021-22 से 2023-24 के दौरान, 20.03.2025 की स्थिति के अनुसार, खंडवा, संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और छत्रपति संभाजी नगर सहित महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में पूरा होने के लिए लक्षित और साथ ही पूर्ण किए गए आवासों/आवास इकाइयों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिले का नाम	**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**	
	लक्ष्य	**पूर्ण किए गए**	**लक्ष्य**	**पूर्ण किए गए**	**लक्ष्य**	**पूर्ण किए गए**
खंडवा जिला (मध्य प्रदेश)	19,444	548	0	16,372	0	1,665
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,103	641	0	1,486	4,838	350
महाराष्ट्र	3,66,479	1,79,021	0	3,43,385	0	1,08,435
छत्रपति संभाजी नगर जिला (महाराष्ट्र)	13,469	5,177	0	10,527	0	3,289

टिप्पणी: एक वित्तीय वर्ष के दौरान आवास निर्माण में पिछले वित्तीय वर्षों के लक्ष्यों की तुलना में हुए निर्माण भी शामिल हैं।